Rehabilitation of families displaced due to establishment of Aluminium Complex in Orissa

2173. SHRI GANESHWAR KUSUM: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the total number of families displaced following the establishment of Aluminium Complex by the National Aluminium Company at Damanjodi and Angul in Orissa; and

(b) the details of the steps taken for the rehabilitation of those displaced families?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF MINES IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): (a) Three hundred seventy five families have so far been displaced on account of establishment of the Alumina Complex at Damanjodi.

Nineteen families have been displaced at Angul on account of establishment of the Aluminium Complex.

(b) The families who have been displaced in Damanjodi have been provided with a residential unit each in the rehabilitation colony near Damanjodi. Two hundred forty persons belonging to these families have so far been given employment directly under National Aluminium Company (NALCO) and further twenty five persons are under training with a view to making them employable in the Company.

In Angul one person from each displaced family has been provided with direct employment in NALCO.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एशियाड खेल गांव में दुकानों की नीलामी

2174. **श्री राम नरेश कुशवाहा :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 20 जनवरी, 1987 को एशियाई खेल गांव में कुछ दुकानों की नीलामी की थी जिसमें ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्तियों से 25 प्रतिशत धनराशि उसी समय जमा कराने और बाकी एक महीने के अन्दर जमा कराने के लिये कहा गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ आबंटितियों ने धनराशि का कुछ भाग एक महीने के अन्दर जमा करा दिया था तथा बाकी रकम की अदायगी अगल महीने में कर दी थी तथा पूरी रकम जमा करा देने के बावजूद अधिकारीगण इस सम्पूर्ण राशि में से 25 प्रतिशत राशि काट कर बाकी 75 प्रतिशत उन्हें वापिस करके उनके आबंटन को रद्द करने की योजना बना रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो जिन व्यक्तियों ने विलम्ब से अदायगी की थी और जिन्होंने सम्पूर्ण राशि भी जमा करा दी है क्या सरकार उनको दुकानों का कब्जा बहाल कराने के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण को आदेश जारी करने का विचार रखती है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इस्पात उद्योग को हानि

2175. **श्री अजीत सिंह :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात के उत्पादन की लागत बढ़ जाने से इस उद्योग में हानि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस हानि से इस उद्योग को बचाने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां। उत्पादन लागत में वृद्धि होना एक कारण है।

(ख) कोयला, बिजली तथा रेल भाड़ा जैसे मुख्य आदानों की लागत में वृद्धि होने के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। इन वृद्धियों की प्रतिपूर्ति करने के लिए क्षमता उपयोग में वृद्धि करने, आधुनिकीकरण द्वारा ऊर्जा की खपत कम करने तथा इस उद्योग की उत्पादकता तथा तकनीकी आर्थिक निष्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

Iron and Steel quota for Punjab

2176. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the Government of Punjab had recently urged the Central Government to raise the ceiling fixed for iron and steel and pig iron quota for the State;

(b) if so, the yearly quantum of iron, steel and pig iron being given to Punjab;

(c) whether Central Government propose to provide adequate quantum of iron quota to Punjab State in view of the scarcity of raw materials in the State; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI M. L. FOTEDAR): (a) Yes, Sir. Government of Punjab had requested for increasing the quantum of iron and steel allocated and supplied to Punjab Small Industries & Export Corporation and the SSI sector during 1987-88.

(b) For 1987-88, 1,50,000 tonnes of pig iron was allocated on account of Punjab Small Industries & Export Corporation. For the first three quarters of 1987-88, 27,309 tonnes of steel have also been allocated in favour of Punjab Small Industries & Export Corporation.

(c) and (d) There is no system of fixation of State-wise quota for allotment of iron and steel materials. These are supplied on the basis of demand registered by the consumers. However, in the case of Small Scale Industries Corporations of States, allocations are made by Development Commissioner for Iron and Steel, based on the demands projected, the past performance in terms of offtake against offers made and the indigenous availability. Considering the increased demand for pig iron, the allocation for 1987-88 has been enhanced from 1,50,000 tonnes to 1,61,000 tonnes. In addition to allocations to the State Corporation, substantial quantities of iron and steel materials are distributed directly to consumers in the State of Punjab by the main producers.

खटीक जाति को अनुसूचित जाति के रूप में माना जाना

2177. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत खटिक समाज की अध्यक्ष ने प्रधान मंत्री से आग्रह किया है कि दक्षिण भारत में खटिक जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाये,

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान 15 अक्तूबर, 1987 के अंग्रेजी दैनिक "हिन्दू" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि उत्तर भारत में खटिक और सोनकर जातियों को अनुसूचित जातियों में सम्मिलित किया गया है ?